



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 5, September 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 6.551

ग्रामीण बैंको की योजनाओं का कृषि एवं कृषकों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन (दौसा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

DR. RAMESH CHAND MEENA

Assistant Professor, Department of EAFM, BBD Govt. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur,

Rajasthan, India

सार

दौसा (Dausa) भारत के राजस्थान राज्य के दौसा ज़िले में स्थित एक नगर है।^{[1][2]}*जिसमें 13 उपखंड है।

यह एक ऐतिहासिक नगर रहा है। सन 1688 में सौख के तोमर जाट राजा बनारसी सिंह ने दौसा के किले को जयपुर और मुगलों से युद्ध में जीत लिया और बाद में महाराजा हठी सिंह ने यहां चौकियां बनाकर जाट राज्य में मिला लिया। यहां कुंतल जाट वीरों की अनेकों छतरियां बनी हुई हैं जो जाट मुगल संघर्ष में जाटों की वीरता को उल्लेखित करती हैं। राजा हठी सिंह ने यहां कुंतलपुर जट्टा नामक गांव बसाया जो आज भी मौजूद है।

कुंतल वंश के जाट राजाओं के समय यह क्षेत्र जटवाड़ा सम्राज्य का हिस्सा रहा था।

दौसा. दौसा अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के तहत रातभर मतगणना होने के बाद सुबह करीब सवा आठ बजे निर्वाचन मंडल ने परिणाम जारी किया। पत्रिका डॉट कॉम सबसे पहले परिणाम की सूचना जारी कर रहा है। निर्वाचन अधिकारी रमेशचंद्र मीणा ने बताया कि श्रीमती अल्का शर्मा, श्रीमती गीतादेवी शर्मा, द्वारकाप्रसाद गुप्ता, धर्मेंद्र शर्मा, पंकजकुमार खण्डेलवाल, बाबूलाल जैन, मदनलाल शर्मा, मयंक शर्मा, श्रीमती रेणू चौधरी व राधेश्याम गुप्ता की निदेशक पद पर जीत हुई। इसके अलावा कपिल राजोरिया व कमलेश मीना पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

परिचय

दौसा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। यह जयपुर से 54 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। दौसा लम्बे समय तक बडगुर्जरो के आधिपत्य मे रहा। दौसा के किले का निर्माण भी गुर्जरों ने करवाया। आभानेरी मे स्थित चाँदबावडी का निर्माण भी इन्ही की देन हैं। दौसा दुल्हेराय को दहेज मे प्राप्त हुआ था। दौसा का नाम पास ही की देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा कच्छवाह राजपूतों की पहली राजधानी थी। इसके बाद ही उन्होंने आमेर और बाद में जयपुर को अपना मुख्यालय बनाया। 1562 में जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत को गए तब वे दौसा में रुके थे। दौसा में ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थान है जो यहाँ के प्राचीन साम्राज्य की याद दिलाते हैं आजादी के बाद सर्व प्रथम जो तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया गया वो दौसा जिले के पास स्थित गांव अलुदा में बनाया गया था। जो दौसा से 10 किमी की दूरी पर है 1947 से पहले, दौसा जयपुर की कच्छवाहा रियासत का हिस्सा था। दौसा व्यापक रूप से दुंढाड के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है। चौहानों ने भी 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस भूमि पर शासन किया था। दौसा को तत्कालीन दुनधार क्षेत्र की पहली राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। चौहान राजा सूध देव ने 996 से 1006 ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन किया। बाद में, 1006 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक, कच्छवाहा राजा दुल्हे राय ने 30 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया।^[1,2,3]

दौसा ने देश को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। टीकाराम पालीवाल और राम करण जोशी उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई और रियासतों के एकीकरण के लिए राजस्थान राज्य बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आजादी के बाद 1952 में टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे।

इसके अलावा, राम करण जोशी राजस्थान के पहले पंचायती राज मंत्री थे जिन्होंने 1952 में विधानसभा में पहला पंचायती राज विधेयक पेश किया था।



कवि सुंदरदास का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को विक्रम संवत् 1653 में दौसा में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध निर्गुण पंथी संत थे और उन्होंने 42 ग्रन्थ लिखे, जिनमें से ज्ञान सुंदरम और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। दौसा क्षेत्र में कछवाहा राज्य के संस्थापक दूल्हेराय ने लगभग 1137 ईस्वी में बड़गूजरो को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। इसे ढूंढाड़ अंचल के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी बनाया गया। दौसा जिले को जयपुर से पृथक कर 10 अप्रैल 1991 को नया जिला बनाया गया।

कृषि में, मोटे तौर पर तीन प्रकार की सहकारी समितियाँ हैं: एक मशीनरी पूल, एक विनिर्माण/विपणन सहकारी, और एक क्रेडिट यूनियन।

- मशीनरी पूल : महंगी कृषि मशीनरी की खरीद को उचित ठहराने के लिए एक पारिवारिक फार्म बहुत छोटा हो सकता है, जिसका उपयोग केवल अनियमित रूप से किया जा सकता है, जैसे कि केवल फसल के दौरान; इसके बजाय स्थानीय किसान मिलकर एक मशीनरी पूल बना सकते हैं जो सभी सदस्यों के उपयोग के लिए आवश्यक उपकरण खरीदता है।
- विनिर्माण/विपणन सहकारी समिति : एक फार्म के पास हमेशा अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए आवश्यक परिवहन के साधन नहीं होते हैं, अन्यथा इसके उत्पादन की छोटी मात्रा उसे बिचौलियों और थोक विक्रेताओं के संबंध में प्रतिकूल बातचीत की स्थिति में डाल सकती है; एक सहकारी एक इंटीग्रेटर के रूप में कार्य करेगा, सदस्यों से आउटपुट एकत्र करेगा, कभी-कभी विनिर्माण का कार्य करेगा, और इसे विपणन चैनलों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डाउनस्ट्रीम में वितरित करेगा।
- क्रेडिट यूनियन: किसानों से, विशेष रूप से विकासशील देशों में, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर वसूल की जा सकती है, या किसानों तक पहुंचने के लिए ऋण भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऋण प्रदान करते समय, ये बैंक अक्सर छोटे ऋणों पर उच्च लेनदेन लागत को ध्यान में रखते हैं, या संपार्श्विक की कमी के कारण ऋण देने से पूरी तरह इनकार कर सकते हैं - विकासशील देशों में यह बहुत गंभीर बात है। ऋण का एक स्रोत प्रदान करने के लिए, किसान एक साथ धनराशि का समूह बना सकते हैं जिसे सदस्यों को ऋण दिया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, व्यक्तिगत किसान की तुलना में सहकारी समिति का बड़ा सहयोगी आकार होने के कारण क्रेडिट यूनियन वाणिज्यिक बैंकों से बेहतर दरों पर ऋण ले सकता है। अक्सर क्रेडिट यूनियन के सदस्य ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए पारस्परिक या सहकर्मी-दबाव की गारंटी प्रदान करेंगे। कुछ उदाहरणों में, विनिर्माण/विपणन सहकारी समितियों के पास अपने व्यापक व्यवसाय के हिस्से के रूप में क्रेडिट यूनियन हो सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण किसानों को बीज और उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण कृषि आदानों तक अधिक सीधी पहुंच प्रदान करता है। इन आदानों के लिए ऋण तब चुकाया जाता है जब किसान अपनी उपज विनिर्माण/विपणन सहकारी समिति को भेजता है। [4,5,6]

कृषि आपूर्ति सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों के लिए कृषि आदानों की खरीद, भंडारण और वितरण को एकत्रित करती हैं। मात्रा में छूट का लाभ उठाकर और पैमाने की अन्य अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग करके, आपूर्ति सहकारी समितियाँ उन इनपुट की लागत को कम कर देती हैं जो सदस्य वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ताओं से सीधी खरीद की तुलना में सहकारी से खरीदते हैं। आपूर्ति सहकारी समितियाँ बीज, उर्वरक, रसायन, ईंधन और कृषि मशीनरी सहित कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करती हैं। कुछ आपूर्ति सहकारी समितियाँ मशीनरी पूल संचालित करती हैं जो अपने सदस्यों को यांत्रिक क्षेत्र सेवाएँ (जैसे जुताई, कटाई) प्रदान करती हैं।

दौसा अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के तहत:-

किसको-कितने मत मिले

श्रीमती अल्का शर्मा को 2035, अशोककुमार गुप्ता को 1067, आलोक शर्मा 1121, कैलाशचंद गुप्ता 934, श्रीमती गीता देवी शर्मा 1366, जगदीशप्रसाद शर्मा 807, दिनेशकुमार पारीक 544, द्वारकाप्रसाद गुप्ता 1359, धर्मेन्द्र शर्मा 1737, पंकजकुमार खण्डेलवाल 1367, पवनकुमार गुप्ता 1055, प्रहलादनारायण गुप्ता ***, बाबूलाल जैन 1407, मदनलाल शर्मा 1360, माया खण्डेलवाल 832, मयंक शर्मा 1499, यशवंतकुमार गुप्ता 1203, रामअवतार गुप्ता 1174, रामकल्याण शर्मा 641, श्रीमती रेणू चौधरी 2057, शंकरलाल शर्मा 1006, संजय गुप्ता 773, सुनिताबेन खूटेटा 930, सुरेशकुमार शर्मा 769 तथा राधेश्याम गुप्ता को 1510 मत मिले।



82 वोट रद्द

सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि बैंक चुनाव के लिए 6 हजार 680 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 3 हजार 955 (59.22 प्रतिशत) मतदाताओं ने वोट डाले। 3 हजार 873 मत वैध पाए गए तथा 82 मत रद्द हुए। रातभर मतगणना, जागते रहे कर्मचारी व प्रत्याशी रविवार को गहमा-गहमी के बीच मतदान हुआ। मतदान के बाद सुरक्षा के बीच दौसा दौसा, लालसोट व बांदीकुई स्थित बूथों से मतपेटियां खान भांकरी रोड स्थित सहकार भवन में लाई गईं। शाम सात बजे बाद मतगणना शुरू हुई। पूरी रात मतगणना चलती रही। प्रत्याशी व कर्मचारी जागते रहे। समर्थकों की धड़कन भी ऊपर-नीचे होती रही। करीब 150 करोड़ के टर्नओवर वाले बैंक के चुनाव दौसा में प्रतिष्ठित हो गए थे। ऐसे में हर किसी की नजर इस पर लगी थी।

चेयरमैन के लिए मारामारी

बैंक के निदेशक मंडल में 12 सदस्य शामिल हो गए हैं। अब सभी निदेशक मिलकर अपने में से ही एक को चेयरमैन चुनेंगे। इसके लिए सोमवार सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। आवश्यकता होने पर शाम 4 से 5 बजे तक मतदान होगा। चेयरमैन बनने के लिए आधा दर्जन निदेशक दौड़-भाग कर रहे हैं। एक-दूसरे निदेशक को अपने पक्ष में करने की जुगत लगा रहे हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है।[7,8,9]

विचार-विमर्श

सहकारी बैंक दौसा अर्थव्यवस्था में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी क्षेत्रों में, वे मुख्य रूप से छोटे उद्योग और स्व-रोज़गार श्रमिकों को सेवा प्रदान करते हैं। वे सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत हैं। वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों पर आवेदन) अधिनियम, 1965 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हैं। [13] अन्योन्या मंडली, 1889 में स्थापित दौसा प्रांत में, भारत का सबसे पहला ज्ञात सहकारी ऋण संघ है।^[14]

दौसा में सहकारी ऋण प्रणाली में अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण संस्थान शामिल हैं। अल्पकालिक ऋण संरचना जो किसानों की अल्पावधि (1 से 5 वर्ष) की ऋण आवश्यकताओं का ख्याल रखती है, अधिकांश राज्यों में त्रि-स्तरीय संरचना है, अर्थात्, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसीसीएस)। जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और कुछ राज्यों में द्विस्तरीय, राज्य सहकारी बैंक और पैक्स। दीर्घकालिक ऋण संरचना किसानों की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं (20 वर्ष तक) को पूरा करती है, यह ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PARDBs) और राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के साथ दो स्तरीय संरचना है। राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। जबकि एसटीसीबी और डीसीसीबी एक सामान्य बैंक की तरह कार्य करते हैं, वे मुख्य रूप से कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक नियामक प्राधिकरण है, दौसा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है और एसटीसीबी और डीसीसीबी के निरीक्षण का ख्याल रखता है। भारत में पहली सहकारी क्रेडिट सोसायटी दौसा में शुरू की गई थी

प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें अन्यथा दौसा सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है, संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं और उनका व्यवसाय वाणिज्यिक बैंकों के समान होता है। उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए नियंत्रण और निरीक्षण प्राधिकारी दोनों है।[10,11,12]

परिणाम

दौसा सहकारी योजनाएं

| क्रमांक | योजनाएं | विवरण |
|---------|---|--|
| 1 | सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 | केंद्रीय सहकारी बैंको से सम्बन्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से रुपये 1.50 लाख तक के लिए गए फसली ऋण का समय या समय से पूर्व चुकारा करने वाले कृषक को राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। |
| 2 | न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना | न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों एवं पीएसएस गार्डिलाइंस के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा दलहन/तिलहन की खरीद की जाती है। रबी सीजन में सरसो / चना तथा खरीफ सीजन में मूंग / मूंगफली / उरद एवं सोयाबीन की खरीद की जाती है। |
| 3 | 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना वर्ष 2022-23 | प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको माध्यम से दिनांक 1-04-2014 एवं इसके पश्चात विवरण दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों का वित्तीय वर्ष 2022 - 23 की ऋण किश्त का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत ब्याज दर में 5 प्रतिशत का अनुदान है, जिससे वित्तीय वर्ष 2022 - 23 हेतु प्रभावी ब्याज दर 5 प्रतिशत से कम हो जाती है। |
| 4 | दौसा ग्राम सेवा सहकारी समितियों / क्रय विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण | कृषि के विकास विकास के लिए सहकारी समितियों में खाद्य बीज एवं दवाईयों के भंडार हेतु राज्य सरकार की बजट घोषणा एवं राज्य एवं केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों / क्रय विक्रय सहकारी समितियों में हेतु शत प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाकर गोदाम निर्माण करवाया जाता है। |
| 5 | दौसा कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना | प्रदेश में किसानों को किराये पर खेती संबंधी यन्त्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों / ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना |
| 6 | राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता योजना | सहकारिता के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
| 7 | दौसा महिला स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण योजन | महिला स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों / सदस्यों को व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं सहकारिता के माध्यम से महिलाओं की सक्रीय भागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्था के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम की क्रियान्विति की जा रही है। |

निष्कर्ष

दौसा. राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजनान्तर्गत दौसा जिले में ऋण वितरण प्रक्रिया की जा रही है. जिसमें काश्तकार 25 हजार से लेकर 2 लाख तक का लोन ले सकता है.

इन लोगों को मिलेगा लोन

सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक शिवदयाल मीना ने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कृषक परिवार जो कृषि और पशुपालन के साथ-साथ अकृषि दस्तकारी गतिविधियों यथा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर भी आजीविका के लिये निर्भर हैं, को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक और स्माल



फाइनेन्स बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा इस हेतु गत वर्ष 100 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है.[13,14,15]

ये होंगे कागजात

सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक शिवदयाल मीना ने बताया कि योजना के तहत भूमिहीन कृषक जो कि किरायेदार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काश्त कर रहे हैं, के परिवार भी पात्र होंगे. आवेदक परिवार को 5 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड होना आवश्यक है.

इतना लोन मिलेगा

सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक शिवदयाल मीना ने बताया न्यूनतम 25 हजार और अधिकतम 2 लाख के ऋण स्वीकृत किये जा रहे हैं. उन्होने बताया कि इस योजना में स्वीकृत ऋण सीमा का प्रतिवर्ष खाते में बकाया राशि जमा करवाकर नवीनीकरण करवाना होगा. योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी निरन्तर ब्याज अनुदान राशि का प्रावधान किया जायेगा . अधिक जानकारी के लिये अपनी नजदीकी बैंक शाखा पर सम्पर्क किया जा सकता है.[16]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Uttar Pradesh in Statistics," Kripa Shankar, APH Publishing, 1987, ISBN 9788170240716
2. ↑ "Political Process in Uttar Pradesh: Identity, Economic Reforms, and Governance Archived 2017-04-23 at the वेबैक मशीन," Sudha Pai (editor), Centre for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, Pearson Education India, 2007, ISBN 9788131707975
3. "Lonely Planet Rajasthan, Delhi & Agra," Michael Benanav, Abigail Blasi, Lindsay Brown, Lonely Planet, 2017, ISBN 9781787012332
4. ↑ "Berlitz Pocket Guide Rajasthan," Insight Guides, Apa Publications (UK) Limited, 2019, ISBN 9781785731990
5. "हमारे बारे में - जिला दौसा - राजस्थान सरकार" । जिला दौसा . 3 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
6. ^ "अध्यक्ष, जिला दौसा, राजस्थान सरकार" । जिला दौसा, राजस्थान सरकार । 2 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
7. ^ "भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की 52वीं रिपोर्ट"(पीडीएफ)। nclm.nic.in। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 25 मई 2017 को मूल(पीडीएफ)से संग्रहीत। 1 जनवरी 2019को लिया गया।
8. ^ "हमारे बारे में - जिला दौसा - राजस्थान सरकार" । जिला दौसा . 21 जून 2022 को पुनःप्राप्त .
9. ^ "इतिहास | जिला दौसा"। जिला दौसा. 3 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त.
10. ^ "दौसा, भारत के लिए मानचित्र, मौसम और हवाई अड्डे" । www.fallingrain.com । 1 फरवरी 2021 को पुनःप्राप्त .
11. ^ "भारत की जनगणना 2001: शहरों, गांवों और कस्बों सहित 2001 की जनगणना का डेटा (अनंतिम)" (पीडीएफ) । भारत का जनगणना आयोग । 25 नवंबर 2020 को लिया गया ।
12. ^ "सी-01: धार्मिक समुदाय द्वारा जनसंख्या" । भारत की जनगणना . 25 जुलाई 2022 को लिया गया ।
13. ^ "पत्थर की नक्काशी ने राजस्थान के सिकंदरा को दी खास पहचान, सालाना 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री" । News18 . 30 अगस्त 2022 । 15 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
14. ^ "दौसा: बसंत पंचमी पर सागर से लग रहे मेले में बाढ़ की भीड़, छठ तक रेस्तरां में रहने वाले ठाकुर जी" । ज़ी न्यूज़ । 2 फरवरी 2022 । 15 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त .
15. ^ "पर्यटन स्थल, जिला दौसा"। जिला दौसा. 15 जुलाई 2022 को पुनःप्राप्त.
16. ^ "दौसा में पर्यटन" । 31 जनवरी 2008 को मूल से संग्रहीत । 23 मई 2011 को पुनःप्राप्त .



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com